स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हिमाचल

हिमाचल दिवस पर मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल का आलेख

प्रो. प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री

पन्द्रह अप्रैल का दिन हम सब हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी दिन 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों के विलय के बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। इस पावन अवसर पर मैं प्रदेश के सभी भाइयो और बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश 62 वर्षों का सफर तय कर अनेक क्षेत्रों में देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर आया है। यह सब यहां के मेहनतकश, ईमानदार एवं कर्मठ लोगों के प्रयासों के फलस्वरूप ही सम्भव हुआ है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।

'सेब राज्य' के रूप में ख्याति अर्जित करने के उपरान्त, आज हिमाचल प्रदेश की पहचान फल राज्य के रूप में होने लगी है। यह प्रदेश देश का 'ऊर्जा राज्य' तथा पहला 'कार्बन न्यूट्रल राज्य' बनने की ओर अग्रसर है। विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हिमाचल प्रदेश, आज अन्यों के लिए आदर्श बन कर उभरा है। एक प्रख्यात साप्ताहिक द्वारा किए गए राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण 'स्टेट ऑफ द स्टेट्स' में प्रदेश को विकास के सात मानकों में प्रथम आंका गया है तथा एक अन्य प्रख्यात साप्ताहिक एवं एक इलैक्ट्रॉनिक चैनल द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश तीन मानकों में सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। यह हिमाचल प्रदेश द्वारा विकास के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों को दर्शाता है।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 1948 में मात्र 240 रुपये थी, आज बढ़ कर 49211 रुपये हो गई है। साक्षरता दर जो 1948 में केवल 8 प्रतिशत थी, आज 83 प्रतिशत तक पहुंच गई है और प्रदेश शीघ्र ही देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य बनने की ओर अग्रसर है। सकल घरेलू उत्पाद भी 27 करोड़ रुपये से बढ़ कर 42788 करोड़ रुपये हो गया है।

'इंडिया टूडे' पत्रिका द्वारा किए गए 'स्टेट आफ द स्टेट्स' सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, मैक्रो इकॉनोमी में सर्वश्रेष्ठ राज्य तथा ओवर-आल परफार्मेंस, पूंजी निवेश तथा मैक्रो इकॉनोमी में 'फास्टैस्ट मूवर स्टेट' आंका गया है। आई.बी.एन.-7 तथा आउटलुक पत्रिका द्वारा करवाये गए सर्वेक्षण में हिमाचल को महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए 'डायमंड स्टेट अवार्ड' प्रदान किया गया है। यह सब इन क्षेत्रों में हो रहे सतत् विकास के साक्षी हैं। इसका श्रेय यहां के मेहनतकश एवं ईमानदार लोगों को तो जाता है, परन्तु समय-समय पर मिले सफल नेतृत्व का भी इसमें योगदान रहा है।

मुझे हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में पहले वर्ष 1998 से वर्ष 2003 तक तथा अब 30 दिसम्बर, 2007 से प्रदेशवासियों की सेवा का मौका मिला है। हमारी सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि विकास की गति में न केवल तेजी लाई जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित बनाया जाए कि विकास की गति में निरंतरता बनाई रखी जाए। हमारा प्रयास है कि गरीब, समाज के उपेक्षित एवं कमजोर वर्गो को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। जब से हमने सत्ता सम्भाली है, प्रदेश का तीव्र एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारा यह प्रयास है कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से आम आदमी पहले लाभान्वित हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की है, जिन्हें अक्षरश: कार्यान्वित किया जा रहा है। सड़क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और स्वरोजगार, स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान हमारा ध्येय है। आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा समाज के उपेक्षित वर्गो के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं युवा कल्याण भी सरकार की प्राथमिकता है।

प्रदेश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि, बागवानी तथा पशुपालन पर निर्भर है तथा प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक नई महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की हैं। इनमें प्रमुख हैं 'पंडित दीन दयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना', जिसके अंतर्गत किसानों को पॉलीहाउस बनाने तथा सूक्ष्म सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में 4.9 लाख वर्गमीटर क्षेत्र पॉलीहाउस के अंतर्गत लाने तथा 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र को माइक्रो सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। यही नहीं सरकार इसमें एक कदम आगे बढ़ी है। इस वर्ष से बांस के पॉलीहाउस के निर्माण पर बी.पी.एल. परिवारों को 90 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है।

किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए विपणन अधोसंरचना को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित किया जा रहा है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1.5 लाख वर्मिग कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गई हैं तथा 10,000 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए पंजीकृत किया गया है। कृषि पैदावार में विविधता लाने तथा जैविक खेती एवं जल प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से 372 करोड़ रुपये की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना को वाह्य वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित किया गया है।

छोटे तथा मझौले किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 4.96 करोड़ रुपये के तकावी तथा भू-सुधार ऋण ब्याज सहित माफ कर 4,32,554 किसानों को लाभान्वित किया है। किसानों को 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर स्टॉप ड्यूटी पर भी छूट दी गई है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें खराब होने पर कोई कठिनाई न हो, इसके लिए सोलन जिला की टमाटर की फसल तथा कांगड़ा एवं ऊना जिलों में आलू की फसल को पायलट आधार पर मौसम आधारित कृषि बीमा योजना के तहत लाया गया है।

प्रदेश में बागबानी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए भी कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। आगामी पांच वर्षो में लगभग 12,500 एकड़ क्षेत्र में पुराने तथा कम पैदावार वाले सेब के पौधों के स्थान पर अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के रूट स्टॉक लगाने के लिए 85 करोड़ रुपये का 'एप्पल रिजूविनेशन प्रोजैक्ट' कार्यान्वित किया जाएगा। इसका प्रावधान हमने इस साल के बजट में रखा है और इसी वर्ष से इस योजना पर कार्य आरम्भ हो जाएगा। सेब तथा आम को भी पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है, उत्पादकों द्वारा देय प्रीमियम का 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले सेब, आम तथा नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है। प्रदेश के फल उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पाद एवं विपणन निगम (एचपीएमसी) द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार के साथ सेब जूस तथा अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं।

ग्रामीणों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। गत वर्ष से 300 करोड़ रुपये की 'दूध गंगा योजना' आरम्भ की है। प्रारम्भ में इसे प्रदेश के मण्डी, सोलन तथा सिरमौर जिलों में आरम्भ किया गया था, परन्तु इस वर्ष से इसको सभी जिलों में शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दुग्ध उत्पादन गतिविधियों से लगभग 50 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन एवं विपणन से संबंधित गतिविधियों के लिए तीन लाख रुपये तक के ऋण सस्ती ब्याज दरों पर प्रदान किए जा रहे है।

'भेड़ पालक बीमा योजना' के अंतर्गत अब तक 8993 भेड़ पालकों को बीमा छत्र प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए, इस वर्ष 'मुख्य मंत्री अरोग्य पशुधन योजना' आरम्भ की जा रही है, जिसके अंतर्गत आगामी तीन वर्षो में उन सभी पंचायतों में पशु औषधालय खोले जायेंगे, जो अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं। प्रदेश के मछुआरों की आर्थिकी में सुधार लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। 6560 मछुआरों को बीमा छत्र प्रदान की गई है, जिसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इसके अंतर्गत दी जा रही राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्र विकास सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरा है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में वर्ष 2008 में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य बना था। गत वर्ष 238 नए पंचायत घरों के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई तथा इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रति इकाई 2 लाख से बढ़ा कर 3 लाख 40 हजार रुपये की गई है। इसके अतिरिक्त, 730 पंचायत घरों को स्तरोन्नत करने के लिए 7.3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 8212 तथा अटल आवास योजना के अंतर्गत 5175 घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत 525 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 4.25 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसमें छोटे तथा सीमांत किसानों को सिंचाई, भू-सुधार एवं बागवानी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश मनरेगा के कार्यान्वियन में श्रेष्ठ कार्य कर रहा है तथा कांगड़ा जिला को इस योजना के तहत बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं को अनेक विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर वे निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें और लघु उद्यम स्थापित कर स्वावलम्बी बन सकें। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दक्षता उन्नयन की दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 3 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से बीपीएल परिवारों के लगभग 3700 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

गरीब लोगों की आवासीय समस्या के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जा है। गत वर्ष अटल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 13000 नए आवासों का निर्माण किया गया है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही सहायता राशि को इस वित्त वर्ष से 38,500 रुपये से बढ़ा कर 48,500 रुपये प्रति इकाई किया गया है।

लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो, अधिकाधिक क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत लाया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गत दो वर्षो में 1,124 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। 2500 हैंडपम्प स्थापित किए गए हैं। जलागम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4,668 करोड़ रुपये की एक वृहद एवं सामरिक महत्व की परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है। 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के विकास के लिए 306 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई गई हैं।

सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत दो वर्षो के दौरान 2103 किलोमीटर लम्बी सड़कों तथा 121 पुलों का निर्माण किया गया, 1655 किलोमीटर लम्बी सड़कों को पक्का किया गया तथा 3091 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर तारकोल बिछाया गया। 890 किलोमीटर लम्बाई के 7 और मार्गो को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का मामला केन्द्र से उठाया गया है। दूरी कम करने के उद्देश्य से सुरंगों का निर्माण करने का भी हमने नीतिगत निर्णय लिया है। 270 करोड़ रुपये की लागत से होली-उतराला, करसेहड़-तेलंग (भूबूजोत) तथा बंगाणा-धनेटा के मध्य तीन सुरंगों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

हम हिमाचल प्रदेश को 'नॉलेज हब' बनाने के लिए प्रयासरत हैं। राज्य में निजी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के 16 विश्वविद्यालय स्थापित करने को अनुमति प्रदान की गई है। सरकारी क्षेत्र में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कांगड़ा जिला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। सोलन जिला में अटल शिक्षा कुंज की स्थापना की गई है, जहां स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। आई.आई.टी. मण्डी की कक्षाएं गत वर्ष आई.आई.टी. रूड़की से आरम्भ की गई हैं तथा इस शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं मण्डी में आरम्भ की जा रही है। कांगड़ा जिला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया गया है।

प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे है तथा सरकार का प्रयास है कि गरीब लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को 30 हजार रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों को गम्भीर बीमारी की स्थिति में स्वास्थ्य बीमा कवर को 1.75 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

राज्य के आई.जी.एम.सी. एवं डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा तथा अन्य अस्पतालों में अधोसंरचना तथा विशेषज्ञ सेवाओं को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। मण्डी में ई.एस.आई. अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। हमरीपुर, सिरमौर तथा ऊना जिलों में निजी क्षेत्र के सहयोग से और मेडिकल कालेज स्थापित करने की योजना है। स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद विभागों में गत दो वर्षो के दौरान 400 से अधिक डाक्टरों के पद तथा नर्सो एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के सैकड़ों पद भरे गए हैं, इनको दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया गया है ताकि लोगों को उपचार करवाने में कोई कठिनाई न हो।

प्रदेश में स्वावलम्बन, स्वाभिमान एवं स्वरोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए गत दो वर्षो के दौरान अनेक प्रभावी कदम उठाए गए है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वर्तमान 6480 मेगावाट विद्युत उत्पादन को बढ़ा कर 17 हजार मेगावाट सुनिश्चित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। जल विद्युत क्षमता के दोहन में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की संयुक्त भागीदारी की नीति को अपनाया जा रहा है। मिनी व माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन में हिमाचली निवेशकों को अधिमान दिया जा रहा है। कुल 100 मेगावाट क्षमता की 26 ऐसी परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है।

प्रदेश सरकार ने बिजली की बचत, बिजली का उत्पादन के मूल मंत्र के साथ कार्य करते हुए राज्य में 'अटल बिजली बचत योजना' का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को चार सी.एफ.एल. बल्ब मुफ्त बांटे गए हैं, जिससे राज्य में वार्षिक 270 मीलियन यूनिट बिजली की बचत सुनिश्चित हुई है। इस पर 80 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। शिमला और हमीरपुर को 'सौर नगरों' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर तथा आय के साधन सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश को पर्यटन गन्तव्य के रूप में प्रोत्साहित कर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए हम 'अन-फॉर्गेटेबल हिमाचल' ब्रांड आरम्भ करने जा रहे हैं। पर्यटन उद्योग को नई दिशा व प्राथमिकता देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साहसिक व तीर्थ पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन देकर आवश्यक अधोसंरचना का सृजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग एक ऐसी योजना तैयार कर रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के गांवों की स्थानीय लोक कथाओं को 'हर गांव की कहानी' के रूप में संकलित एवं प्रकाशित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं ऐतिहासिक लोक कथाओं के प्रति वर्ष भर आकर्षित किया जा सके।

प्रदेश को आय सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक विकास को अधिमान दिया जा रहा है। प्रदेश में 7464 बीघा भूमि का 'लैंड बैंक' सृजित किया गया है ताकि यहां पर उद्योगों को स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों को भूमि उपलब्ध करवाई जा सके। प्रदेश में स्थापित की जा रही सभी नई औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। गत दो वर्षो के दौरान राज्य में 11 हजार करोड़ रुपये निवेश की 2061 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 92 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेशकों के लिए प्रदेश में सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति, मूलभूत, गुणात्मक अधोसंरचना तथा प्रदूषणमुक्त व शांतिप्रिय माहौल कुछ ऐसे आकर्षण है, जो प्रतिष्ठित उद्यमियों को यहां उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना आकार की 33.69 प्रतिशत राशि सामाजिक क्षेत्र को आबंटित कर सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश बीस सूत्री कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में नवम्बर, 2009 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया है तथा हमें विश्वास है कि प्रदेश यह स्थान बनाए रखेगा। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत, राज्य में ऐसे क्षेत्रों जहां 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते है, में आधारभूत सुविधाएं सृजित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष के दौरान 742 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

15,234 अतिरिक्त पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कर प्रदेश में 2.62 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इस पर 110 करोड़ रुपये सालाना व्यय किए जा रहे हैं। योजना के तहत वार्षिक पात्रता के लिए आय सीमा को व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए 6 हजार रुपये से बढ़ा कर 9 हजार रुपये तथा परिवार के लिए 10,000 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपये किया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण व सम्मान के उद्देश्य से बी.पी.एल. परिवारों के लिए 'बेटी है अनमोल' योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत इन परिवारों की दो बालिकाओं तक उनके नाम जन्म पर ही प्रदेश सरकार 5100 रुपये प्रति बेटी जमा करवाएगी। सरकार ने इस वर्ष से बी.पी.एल. परिवारों की दस जमा एक व जमा दो की छात्राओं को 1500 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने का भी निर्णय लिया है। इससे पहले यह छात्रवृत्ति दसवीं कक्षा तक की छात्राओं को ही प्रदान की जाती थी।

प्रदेश सरकार पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के प्रति संवेदनशील है और इस दिशा में पहल करते हुए अनेक पर्यावरण संरक्षण उपाये किए जा रहे हैं। प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा को बचाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम प्रदेश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर हिमाचल को 'कार्बन न्यूट्रल राज्य' बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने हाल ही में कोस्टारिका का दौरा कर वहां इस दिशा में किए जा रहे कार्य का अध्ययन किया है ताकि वहां किए गए अच्छे कार्यो का अनुसरण कर हिमाचल में भी अपनाया जाए। वाशिंगटन में विश्व बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक कर इस बारे में विचार-विमर्श किया गया। विश्व बैंक ने हमारे आग्रह पर राज्य की 602 पंचायतों में चलाई जा रही मिड-हिमालय वाटर परियोजना को अन्य पंचायतों में आरम्भ करने में रूचि दिखाई है। इस पर 2400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश रिसाइकल्ड प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 2 अक्तूबर, 2009 से प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस वर्ष के अंत तक प्लास्टिक पैकेजिंग पर भी प्रतिबंध लगाने के प्रयास जारी है। हमने सड़कों को पक्का करने में पर्यावरण मित्र तकनीक से प्लास्टिक कचरे का प्रयोग आरम्भ किया है। प्रदेश में 'पालिथीन हटाओ- पर्यावरण बचाओ अभियान' का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिले हैं।

हमारी सरकार लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी तथा कुशल प्रशासन प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। जन शिकायतों के त्वरित निवारण को सुनिश्चित किया जा रहा है। जन शिकायतों को ऑन-लाइन दर्ज कर शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैब आधारित विशेष साफ्टवेयर तैयार कर सभी विभागों में आपरेशनल बनाया गया है। लोगों की शिकायतों को घरद्वार पर निपटाने के लिए राज्य के सभी भागों में 'प्रशासन जनता के द्वार' शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मैंने कई स्थानों पर 'प्रशासन जनता के द्वार' शिविरों में भाग लिया है।

हिमाचल प्रदेश की हमारी परिकल्पना बिल्कुल स्पष्ट है। हम प्रदेश के तीव्र एवं समान विकास के लिए दृढ़संकल्प है और एक ऐसे हिमाचल प्रदेश की स्थापना के लिए प्रयासरत है, जहां लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर हों, प्रदेश तथा प्रदेशवासी स्वावलम्बी हों और प्रदेशवासी आत्म-सम्मान से जीवन यापन कर सकें। हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर आओ हम सब मिलकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ने का संकल्प लें।

जय हिन्द! जय हिमाचल!

प्रदेश में स्वावलम्बन, स्वाभिमान एवं स्वरोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक वर्तमान 6480 मेगावाट विद्युत उत्पादन को बढ़ा कर 17 हजार मेगावाट सुनिश्चित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। जल विद्युत क्षमता के दोहन में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की संयुक्त भागीदारी की नीति को अपनाया जा रहा है। मिनी व माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के आंबटन में हिमाचली निवेशकों को अधिमान दिया जा रहा है। कुल 100 मेगावाट क्षमता की 26 ऐसी परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है।

हम हिमाचल प्रदेश को 'नॉलेज हब' बनाने के लिए प्रयासरत हैं। राज्य में निजी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के 16 विश्वविद्यालय स्थापित करने को अनुमति प्रदान की गई है। सरकारी क्षेत्र में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कांगड़ा जिला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। सोलन जिला में अटल शिक्षा कुंज की स्थापना की गई है, जहां स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। आई.आई.टी. मण्डी की कक्षाएं गत वर्ष आई.आई.टी. रूड़की से आरम्भ की गई हैं तथा इस शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं मण्डी में आरम्भ की जा रही हैं। कांगड़ा जिला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश की हमारी परिकल्पना बिल्कुल स्पष्ट है। हम प्रदेश के तीव्र एवं समान विकास के लिए दृढ़संकल्प हैं और एक ऐसे हिमाचल प्रदेश की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं, जहां लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर हों, प्रदेश तथा प्रदेशवासी स्वावलम्बी हों और प्रदेशवासी आत्म-सम्मान से जीवन यापन कर सकें। हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर आओ हम सब मिलकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ने का संकल्प लें।